

जयपुर दौरे पर आए भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का भव्य स्वागत

नड्डा भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने आए हैं

जयपुर, 23 जनवरी (का.सं.)। भाजपा राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित करने जयपुर आये भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया ने राजस्थानी साफा और पार्टी

है। मगर मेरा मानना है कि सभी को नेता बनना चाहिए। पद अपने आप मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने में सुंदर सिंह भंडारी, भैरोसिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी के योगदान को



भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने सोमवार को जयपुर में राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति की बैठक ली। उनके साथ बी.जे.पी. प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे।

■ प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर भी जोरदार हमला बोला और आह्वान किया कि आगामी चुनावों में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है।

■ नड्डा ने कहा कि, जनसंघ से लेकर भाजपा तक राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने में सुंदर सिंह भंडारी, भैरोसिंह शेखावत, भंवर लाल शर्मा और ललित चतुर्वेदी के भारी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

का दुष्टा पहनाकर जेपी नड्डा का स्वागत किया।

भाजपा राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति बैठक को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया और कहा कि वीरों की भूमि मरुधरा पर भव्य आत्मिक स्वागत-अभिनंदन के लिए राजस्थान के करोड़ों कार्यकर्ताओं और पावन धरा राजस्थान को बंदन वंदन प्रणाम करता हूँ। भाजपा राजस्थान इकाई द्वारा किए गए तमाम आंदोलनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए मैं प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश टीम और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। नड्डा ने कहा कि हर किसी को विधायक और सांसद बनने की चाहत

कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, पॉलिटिक्स विद मिशन, पॉलिटिक्स विद आईडियोलॉजी के साथ हम काम करते हैं, देश की सेवा, पार्टी और विचारधारा हमारे लिए सर्वोपरि है। लक्ष्य हमेशा विचारधारा की मजबूती का लेकर चलें, कैडर की मजबूती का लेकर चलें, क्योंकि हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कैडर मजबूत होगा तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे, पार्टी मजबूत होगी तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे, पार्टी सर्वोपरि है।

नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है और हम प्रजातांत्रिक तरीके से कैडर की मजबूती के लिए कार्य

करते हैं, भाजपा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है बाकी सभी पार्टियां फैमिली पार्टी बनकर रह गई हैं, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, एक फैमिली की पार्टी के रूप में कांग्रेस को पहचान बन चुकी है, रीजनल पार्टियां भी फैमिली पार्टी बन कर रह गई हैं।

कांग्रेस को यही नहीं पता कि वह किसको जोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे

हैं, राहुल गांधी की पूरी यात्रा में दाएं बाएं वही लोग चले जिन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाए, भारत के खिलाफ साजिशों को।

भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात के लिए संकल्पित हूँ कि अंतिम सांस तक पार्टी के लिये कार्य करूंगा, सर्वस्वश्री और सर्व समावेशी लक्ष्य के साथ काम करूँ। बड़े लक्ष्य के

लिए बड़ा दिल लेकर और बड़े मन से कार्य करें और मिशन 2023 और 2024 के लिए संकल्पित होकर कार्य करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2023 में राजस्थान और 2024 में केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बने इसके लिए पूरी मजबूती से कार्य करें।

उन्होंने कहा कांग्रेस की अशोक

गहलोत सरकार के शासन में राजस्थान के बदतर हालात हैं, जिसमें महिला क उद्देश्य जीवन को एक उत्सव की भांति अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी जनविरोधी और कुशासन देने वाली कांग्रेस सरकार को हमें उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़नी है, इसकी जनता के बीच जाकर एक्सपोज करते रहना है।

‘कमियों के बावजूद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लोकतंत्र के समान है जिसमें यह सभी खराब प्रणालियों के बीच एक सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि एक मात्र अन्य विकल्प नेशनल जूडोशियल अर्थाईन्टेंटेंस कमीशन (एन.जे.ए.सी.) है, लेकिन कोलोनीयलिस्ट सिस्टम इससे कम बुरा है।

श्रीधर अदालत में वर्ष 1993 में नरिमन ने ही एन.जे.ए.सी. का विरोध किया था। बार एण्ड लीगल बैरसाइट को दिए एक साक्षात्कार में नरिमन ने कहा कि “उन्होंने तर्क दिया था कि जजों की नियुक्ति जजों द्वारा नहीं की जानी चाहिए,

लेकिन इस मुद्दे से बाद में जिस तरह से निबटा गया और विवाद पैदा हो गए, उसके आधार पर मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि कोलोनीयलिस्ट ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।”

जब उनसे कोलोनीयलिस्ट की जड़ियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरी कवायद यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि सिस्टम के अन्तर्गत सबसे बेहतर व्यक्ति को नियुक्ति मिले और जजों द्वारा कुछ जजों का चयन किए जाने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ऐसा हमेशा से हुआ है और आखिरकार जज भी तो मानव हैं।

भाजपा तमिलनाडू में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जो उसके प्रति सहानुभूति रखने वाला हो।

इस चैनल की लॉचिंग भाजपा की तमिलनाडू इकाई करेगी। ऐसी संभावना है कि यह टी.वी. चैनल “जनम टी.वी.” का ही विस्तार (एक्सटेंशन) होगा, जो केरल में भाजपा की आवाज माना जाता है। यह चैनल चेन्नई में अल्कार गेट के बाहर किसी स्थान पर क्लब करेगा। चेन्नई के मीडिया विश्लेषकों का कहना है कि यह कोई चौकाने वाली चीज नहीं है। अगर यह चैनल व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं भी रहता है, तो भी उसे काफी सहयोग एवं सम्बल मिल जायेगा क्योंकि भाजपा दिल्ली में सत्तारूढ़ है।

भाजपा की तमिलनाडू इकाई के अध्यक्ष के. अन्नमलाई इस टी.वी. चैनल प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक एवं उत्साहित हैं, जो भाजपा की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को व्यापक कवरेज देगा तथा 4 अप्रैल 2023 को शुरू होने जा रही उनकी राज्यव्यापी पदयात्रा को पूरी तवज्जो देते हूये, उसका प्रचार-प्रसार करेगा।

प्रसंगिक बात दें कि केरल में भी, जनम टी.वी. ने लोकल मीडिया में पार्टी का पला भारी रखा था तथा सबरीमाला केस को इसके द्वारा ही महत्ता के फलस्वरूप, इसके दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी तथा मुख्यधारा के मीडिया चैनलों की प्रतिस्पर्धा में आ गया था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की एकमात्र प्राथमिकता चिकित्सा तथा मरीजों एवं डॉक्टरों के हित होने चाहिए। फेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रोहनकृष्णन ने कहा, “मेरे ख्याल से तो एन.एम.सी. एवं स्वायत्तशासी, स्वतंत्र तथा राजनीति-निरपेक्ष निकाय की तरह काम नहीं कर रहा है। डॉ. कृष्णन, मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, जो केन्द्र सरकार का कॉलेज है, में ऑर्थोपैडिक सर्जन हैं।

उन्होंने कहा, “दुख का विषय है कि कमीशन, जिसकी स्थापना मैडिकल शिक्षा में सुधार तथा हर जगह हर व्यक्ति के लिये चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी, ने इस प्रकार का संकुलर जा रही है। इस प्रकार का कोई भी संकुलर प्रदर्शित करता है कि एन.एम.सी. अफसरशाही तथा पी.एम.ओ. को खुश करने की कोशिश कर रहा है।”

दो अन्य फेमा-सदस्यों ने कहा कि एन.एम.सी. को चिकित्सा-सुविधा एवं सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करने पर ध्यान देना चाहिए।

एक तरफ, डॉ. स्वस्थ क्षेत्र के लिये बजट-आवंटन कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ, अन्य सरकारी विभाग “सरकार के प्रति व्यादा निष्ठा” दिखा रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सिंघानिया की शीर्ष प्राथमिकताएँ होनी उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार, केन्द्र द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च, जो 2016-17 में भारत की

जी.डी.पी. का 1.09 प्रतिशत था, गिरकर 2017-18 में 0.97 प्रतिशत तथा 2018-19 में 0.96 प्रतिशत रह गया। लक्ष्यप्रतिष्ठ समाज विज्ञानी आनंद बैतिलि ने कहा कि सरकार का रेग्युलेटरी के लिये अनुचित है कि वह विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम को देखने के लिये संकुलर जारी करे।

बैतिलि ने कहा, “संस्थाएं यह निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होनी चाहिये कि वे विद्यार्थियों या फैकल्टी के लिये क्या कार्यक्रम आयोजित करना चाहती हैं। सरकार द्वारा रेग्युलेटरी बाँधी को ऐसा जाने तथा रेग्युलेटर्स द्वारा संस्थानों को ऐसा कहे जाने की प्रवृत्ति गलत एवं अस्वस्थ (परम्परा की शुरुआत) है।

पोस्ट प्रेज्यूट कर रहे मैडिकल छात्र कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जो चिकित्सकों और रोगियों, दोनों को प्रभावित कर रहा है। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेस (एएमएस) के एफ रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि “रेजिडेंट्स की कमी का मतलब है कि डॉक्टरों प्रत्येक रोगी को कम समय देने के लिए बाध्य हैं।”

रेजिडेंट ने आगे कहा कि “हेल्थ केयर में कम व्यय, मानव संसाधन और चिकित्सकों की सुरक्षा नेशनल मैडिकल कमीशन की शीर्ष प्राथमिकताएँ होनी चाहिए ना कि स्क्रीनड इवैन्स का प्रोत्साहन।

एक केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान के

एक प्रोफेसर ने कहा कि विडम्बना यह है कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार पर जोर दे रही है और साथ ही शिक्षा के लिए फण्ड्स में भी कमी कर रही है।

प्रोफेसर ने नाम ना छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि “सरकारी विश्वविद्यालयों के पास फण्ड्स की कमी है। फण्डिंग में प्रत्येक वर्ष वास्तविक कमी आ रही है।” फिर भी सरकारी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नियामक संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सरकार की गलत प्राथमिकताओं को झलक दिखाई देती है। एफ.ए.आई.एम.ए. में चर्म रोग विशेषज्ञ एवं सलाहकार मनीष जांगड़ा ने कहा कि “राजधानी तक के सरकारी अस्पतालों में दवाईयां, उपकरण और स्टाफ की कमी है और एन.एम.सी. हेल्थ केयर में दवागत सुधार करने के बजाए प्रचार में भाग ले रहा है।”

शिक्षा मंत्रालय ने “परीक्षा में चर्चा” को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित संवाद के एक ऐसे कार्यक्रम की संज्ञा दी है जिसमें वे परीक्षा संबंधी घबराहट और स्कूल के बाद के जीवन पर देश और विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से वार्तालाप करते हैं।

कार्यक्रम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होगा। इसके लिए 150 मंत्रों के 3.1 मिलियन से अधिक विद्यार्थियों और 5 लाख 60 हजार शिक्षकों के अलावा 50 देशों के 1 लाख 95 हजार अभिभावकों ने

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। मंत्रालय ने कहा है कि “कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन को एक उत्सव की भांति मनाने को लेकर तनाव पर पार पाने में मदद करना है।”

मीडिया पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2015 के एक निर्णय की याद दिलाई जिसमें आई.टी. एक्ट की धारा 66ए को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि अनजाने में हुई गलतियां तर्कसंगत प्रतिबंधों का आधार नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पी.आई.बी.) ऑनलाइन “फेक न्यूज” को लेकर चेतावनी देता रहा है, लेकिन उसकी समझ को कई बार गलत पाया गया। उन्होंने कहा कि यदि मसौदा ही कानून बन जाता है तो ऐसी गलत राय को पलटा नहीं जा सकेगा क्योंकि इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

लोकतांत्रिक नियम बनाए रखन को लेकर आई.जे.यू. ने कहा कि सरकार को ऑनलाइन गलत जानकारी या दुष्प्रचार पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन करना चाहिए उसने आगे कहा कि “फिर भी लिखिक रूप से निर्धारित किसी विषय के नियमन का काम किसी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण का होना चाहिए ना कि सरकार का।”

महारानी कॉलेज छात्रसंघ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने थप्पड़ मार कर नीचे गिरा दिया। घटना को लेकर दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और मंच पर तोड़फोड़ कर दी। उधर कॉलेज प्रशासन और निर्मल चौधरी की ओर से घटना को लेकर अशोक नगर थाने में अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराए गए हैं।

कार्यक्रम समाप्ति से कुछ देर पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी मंच पर पहुंचे। इस दौरान महासचिव अरविंद जाजड़ा ने निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारकर मंच से धक्का दे नीचे गिरा दिया। इस घटना के बाद निर्मल समर्थक आक्रोशित हो गए और उन्होंने मंच पर चढ़कर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य लोग मंच पर ही मौजूद थे। देखते ही देखते निर्मल समर्थकों ने मंच को पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां लगी टेबल, कुर्सी, नेम प्लेट, साउंड सहित सबको नीचे फेंक दिया। इस दौरान निर्मल और जाजड़ा समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई। हंगामे को देखकर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य अतिथि मंच से उतरकर चले गए। पूरी घटना को वहां मौजूद पुलिस और कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखा रहा। गनीमत रही कि मंच पर मौजूद केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य अतिथियों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई।

जिस समय यह घटना हुई कार्यक्रम समाप्ति पर था। कुलपति प्रो. राजीव जैन समापन भाषण दे रहे थे। इसी बीच आर्यु छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी समर्थकों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंच पर पहुंचे। निर्मल मंच से हाथ हिलाकर छात्रों का अभिवादन कर रहे थे, कि इसी दौरान जाजड़ा ने निर्मल को थप्पड़ मारकर मंच से गिरा दिया।

घटना के बाद निर्मल चौधरी ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में पुलिस के सामने असामाजिक तत्व इस प्रकार गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे हालात पहले नक्सली क्षेत्रों में थे, जैसे अब राजस्थान में होते जा रहे हैं। यह पुलिस प्रशासन की नाकामी का परिणाम है। मुझे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए बुलाया गया था मैं इस घटना से डरने वाला नहीं हूँ, छात्र शक्ति के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। इधर निर्मल चौधरी की तरफ से अशोक नगर थाने में अरविंद जाजड़ा के खिलाफ मारपीट का जबकि कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों के खिलाफ मारपीट व तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

कार्यक्रम में हंगामा होने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शेखावत के निकलने के साथ ही कुलपति प्रो. राजीव जैन और कॉलेज प्राचार्य प्रो. मुक्ता अग्रवाल सहित अन्य विश्वविद्यालय शिक्षक भी चले गए। प्रो. मुक्ता अग्रवाल अपने ऑफिस में आकर बैठ गईं, वहीं कुलपति की विश्वविद्यालय चले आए। जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वे मौके पर उपस्थित होकर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते। उनके जाने के बाद भी छात्रों की बीच मारपीट होती रही। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद छात्राएं दहशत में आ गईं।

इस घटना के बाद निर्मल का एक वीडियो पुलिस के बीच जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो उस समय का है जब छात्रसंघ चुनाव की मतगणना के बाद जब निर्मल चौधरी छात्रसंघ अध्यक्ष पद विजयी हुए थे। विजयी होने के बाद पुलिस जवान शपथ दिलाने के लिए निर्मल को लेकर जा रहे थे। उस दौरान

■ कॉलेज प्रशासन ने भी कार्यक्रम में छात्रों द्वारा मारपीट करने और मंच पर तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कराया है।

■ दुखद बात यह भी है कि, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मंच पर मौजूद थे, जब यह घटनाक्रम हुआ।

निर्मल पुलिस को धमकते हुए दिख रहे हैं।

कार्यक्रम में हंगामा होने के बाद एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हुशयार मीणा कार्यकर्ताओं के साथ महारानी कॉलेज पहुंचे। महासचिव अरविंद जाजड़ा को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के छात्र प्रिंसिपल प्रो. मुक्ता अग्रवाल के चैबर में घुस गए। इस दौरान पुलिस छात्रों को खदेड़कर बाहर ला रही थी, तभी धक्का-मुक्की में सीआई नेमीचंद सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उनके ऊपर एक छात्र भी गिर गया। नेमीचंद सिविल ड्रेस में थे, इस इस कारण पुलिस जवान भी उन्हें पहचान नहीं पाए और उन पर भी लाठीचार्ज कर दिया। गिरने से नेमीचंद के पैर में भी चोट आई है।

एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हुशयार मीणा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना का विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। दोनों ही पार्टी के नेताओं को भी कॉलेज व विश्वविद्यालय कैम्पस में इस प्रकार के कार्यक्रम में आने से बचना चाहिए। वहीं अध्यक्ष और महासचिव दोनों का ही बराबर का अधिकार है, दोनों को ही मंच पर समान रूप से बिदना चाहिए। महारानी कॉलेज में छात्रों के प्रवेश पर रोक है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने बाहरी छात्रों सहित विश्वविद्यालय के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश देकर कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। छात्रसंघ पदाधिकारियों के साथ भी बढ़ी संख्या में छात्र वहां पहुंच गए। अगर बाहरी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता तो, इस घटना को होने से रोका जा सकता था। वहीं केन्द्रीय मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। महारानी कॉलेज में जब भी छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम होता है, तो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। कोरोना से पहले भी तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष रिंतु बाला के कार्यालय उद्घाटन के दौरान हंगामा हुआ था।

महाराष्ट्र के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) केस में दी गई जमानत की पुष्टि की जाती है। इसके बाद, बैंच इस याचिका को सस्सरी तौर पर खारिज करने लगी तथा यह स्पष्ट भी कर दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा किये गये विचारों से ट्रायल प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वे विचार केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं। देशभूय 2 नवम्बर, 2021 को हुई उनकी गिरफ्तारी के दिन से ही हिरासत में हैं। अक्टूबर, 2022 में, बम्बई उच्च न्यायालय ने मनीलाण्डरिंग के एक केस में पूर्व गुज मंत्री को पहले ही जमानत दे दी थी। उस जमानत को रद्द करने से भी सर्वोच्च न्यायालय ने इंकार कर दिया था। देशभूय एक अन्य सी.बी. आई. केस के सिलसिले में जेल में थे।

कोटपूतली में तोड़फोड़ की घटनाओं का दौर फिर शुरू

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे में नगर परिषद द्वारा कोटपूतली के मास्टर प्लान 2011-31 को लागू करने और सड़क चौड़ी करने के नाम पर पुलिस नगर पालिका तिराहे से आजाद चौक मार्ग के बीच बनी करीब 15 संरचनाओं को ध्वस्त किया।

गौरतलब है कि विगत अगस्त माह से परिषद द्वारा मुख्य चौराहे से पुरानी नगर पालिका तिराहे तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के नाम पर व पूतली कट से बानसूर मोड खण्ड के सरदार

■ पुरानी नगर पालिका तिराहे से तहसील परिसर आजाद चौक मार्ग पर चला नगर परिषद का पीला पंजा।

■ कोटपूतली में मास्टर प्लान के तहत संरचनायें तोड़ने का मामला, 15 संरचनाओं को ध्वस्त किया।

■ व्यापारी सूर्यकांत बिदाणी का इस कार्रवाई से सुरक्षा पाने के लिए मुंसिफ कोर्ट में दर्ज मामला लंबित था, प्रशासन ने उनकी भी दुकान तोड़ दी और घटनास्थल से जबरदस्ती उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया।

स्कूल से शनि मंदिर तक की सड़क को 60 फीट चौड़ा करने के नाम पर भी कई इमारतों को गिराया था। यहां यह भी गौरफरमाने योग्य है कि इस कार्रवाई के खिलाफ करीब 100 से भी अधिक मामले में हाईकोर्ट में लंबित हैं। क्योंकि कार्यलय दुकानदार व मकान मालिकों का कहना है कि नगर परिषद ने कार्रवाई करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया है।

उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान

कार्यवाही के चतुर्थ चरण में पुरानी नगर पालिका तिराहे से आजाद चौक स्थित कचहरी परिसर के मार्ग को 40 फीट किया जाना है। वहीं आजाद चौक से अतिरूपाण हटाकर उसे पुराने मूल स्वरूप में लाना है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पूर्व संरचनाओं में बाधक बन रही 73 संरचनाओं को

तोड़फोड़ से प्रभावित व्यापारियों व मकान मालिकों में रोष व्याप्त

नेतृत्व में कार्मिकों समेत पुलिस का भारी जापा उक्त मार्ग पर सोमवार तड़के पहुंचा, जहां निर्माण हटायें गये।

कस्बे के आजाद चौक में एक कथित निर्माण को हटाने के दौरान नगर परिषद अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान परिषद

ने कचहरी के मुख्य द्वार पर निर्माणों को हटायी तो दुकान मालिक व्यापारी सूर्यकांत बिदाणी ने एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाते हुए भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने पहले तो उसे पीटा फिर हिरासत में ले लिया। व्यापारी का कहना है कि तोड़फोड़

की कार्रवाई से सुरक्षा पाने के लिए उन्होंने कोटपूतली मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका भी दायर कर रखी है, जिसकी सुनवाई 23 तारीख को हो थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें इस अदालत से अंतरीम रोक के आदेश प्राप्त नहीं हुए।

उन्होंने आगे बताया कि कोर्ट में

मामला लंबित होने के बावजूद नगर परिषद ने सुबह 6 बजे आकर उनकी दुकान को ध्वस्त कर दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जोर जबरदस्ती से खींचकर, मुजरिमों की माफ़त साढ़े 6 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि उनकी गुहारों

का किसी भी अधिकारी पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उनके आत्मसम्मान, आत्मबल को कुचलते हुए पुलिस उन्हें घसीटते हुए थाने ले गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से उनकी मानहानि हुई है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी दुकान के अन्दर पड़े सामान को किसी भी



कोटपूतली नगरपालिका ने आजाद चौक पर सड़क किनारे बनी इमारतों और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की।



कोटपूतली नगरपालिका ने सोमवार को तहसील कार्यालय के गेट के सामने बनी सूर्यकांत बिदाणी की दुकान तोड़ दी। सूर्यकांत बिदाणी की दुकान का मामला कोटपूतली मुंसिफ अदालत के समक्ष लंबित था। इन्होंने कार्यवाही के वक्त अपना सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किये लेकिन प्रशासन ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। सूर्यकांत बिदाणी ने प्रशासन के कर्मचारियों के समक्ष खूब मित्रत्वं की वे बेबस और असहाय होकर रोने लगे। पुलिस ने बाद में सूर्यकांत बिदाणी को हिरासत में ले लिया।